fishing zones (PFZ), using satellite data, is disseminated to the coastal fishermen and establishment of fishing vessel to shore communication system, are implemented by the Department of Ocean Development in coordination with the State Governments. The State Governments are responsible for dissemination of the PFZ information, management and maintenance of the FAX facility provided by the Government of India for receipt of PFZ information, provision of infrastructure for setting up of a VHF tower and transreceiver system at the shore stations for establishing fishing vessel to shore communication system, management and maintenance of the system.

(c) and (d) The following are the ongoing projects in Tamil Nadu :

(i) Marine Satellite Information Service : Under the scheme the potential fishing zone maps derived from satellite data are disseminated to the coastal fishermen. A MARSIS Centre has been established at the Institute for Ocean Management, Anna University.

(ii) A National Institute of Ocean Technology is established in the Indian Institute of Technology, Madras.

(iii) Monitoring of marine pollution along parts of the Tamil Nadu coast.

(iv) Under the programme of providing fishing vessel to shore communication system, two shore stations at Nagapattinam and Tuticorin are proposed to be commissioned.

DEVELOPMENT OF MAHABALIPURAM UNDER OCEAN DEVELOPMENT SCHEME

3224. SHRI MISA R. GANESAN :
SHRI J. S. RAJU :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have plans to develop Mahabalipuram under ocean development scheme in Tamil Nadu;

(b) if so, what is the total amount to be spent on this scheme; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) The Government of India do not have any plans to develop Mahabalipuram under ocean dvelopment scheme.

(b) Does not arise.

(c) The Development of shore areas like Mahabalipuram falls within the purview of the State Government.

NEED TO PROMOTE PRODUCTION AND EXPORT OF SEAFOOD

3225. SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that, in view of the increasing levels of health consciousness in the world, the demand for seafood has increased; and

(b) if so, what steps Government intend to take to promote ecologically sound production and export of seafood as country has an extensive coastline and access to a large exclusive economic zone ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO

FALEIRO) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राष्ट्रीय छुट्टियां

*3226. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छुट्टियां किस-किस तारीख को मनाई जाती हैं और उनमें से प्रत्येक का क्या महत्व है ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रीराम के जन्म दिवस को राष्ट्रीय छुट्टियों में शामिल नहीं किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार देश के करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए श्रीराम के जन्म-दिवस को राष्ट्रीय छुट्टियों में शामिल करेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य (मंत्री) (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और 2 अक्तूबर (महात्मा गांधी का जन्म दिवस)।

(ख) जी हां ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के साथ विचार-विमर्श

3227. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भाषा संरक्षण संगठन के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए आमन्त्रित किया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी किसी रिपोर्ट में संसद्रीय संकल्प को लागू करने के संबंध में कोई सिफारिश की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

*पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1746, 15 दिसम्बर 1993 के स्थानांतरित ।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन की मांगों का संबं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के प्रयोग तथा उनमें अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न पत्र को समाप्त करने से भी है । इन मुद्दों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा. सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है तथा समिति की सिफारिशों तथा उन पर संघ लोक सेवा आयोग की राय पर सरकार द्वारा अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

संघ लोक सेवा आयोग के सामने "सत्याग्रह"

3228. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सामने कोई सत्याग्रह चल रहा है; यदि हां, तो यह आंदोलन कब से चल रहा है और आंदोलन को संचालित करने वाले संगठन का नाम क्या है; और उनकी मांगें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे सत्याग्रहियों के तम्बू इत्यादि तहस-नहस कर दिए हैं;

(ग) क्या पुलिस ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे सत्याग्रहियों को हथकड़ी पहनाकर किसी मर्यादा का उल्लंघन किया है; यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने सत्याग्रहियों को सुरक्षा और राशन, बिजली तथा पानी जैसी प्राथमिक सुविधाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन नामक संगठन सन् 1988 से संघ लोक सेवा आयोग के बाहर सत्याग्रह पर है। उनकी मांगें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के